


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

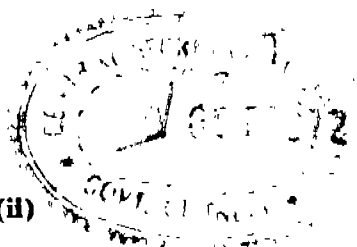
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 390] नई दिल्ली, बुधवार, सितंबर 1, 1972/भाद्र 0, 1894

No. 390] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972/BHADRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September 1972

S.O. 569(E).—Whereas the Naga National Council (hereinafter referred to as the Council)—

- (i) has openly declared as its objective the formation of an independent Nagaland, comprising the State of Nagaland and the adjacent Naga-inhabited areas of Assam, Manipur and Arunachal Pradesh (hereinafter referred to as the said areas);
- (ii) has raised an armed force, namely, the so-called Naga Army, and has set up, and is using, the organisations specified in the Schedule below to achieve the said objective and to bring about the secession of the said areas from the Union of India;
- (iii) is, in furtherance of its objective aforesaid, employing the so-called Naga Army in attacking the Security Forces, the Civil Government and the citizens in the said areas and indulging in acts such as arson, looting, intimidation of the civil population and forcible collection of funds and food-stuffs;
- (iv) has, to achieve its objective aforesaid, maintained contacts, through the so-called Federal Government of Nagaland with foreign countries, with a view to securing financial and armed assistance and training facilities for the so-called Naga Army; and

- (v) has instigated, advised and aided certain individuals and groups in the north-eastern region of India, with the object of developing a co-ordinated insurgency movement to achieve secession of the said region from the Union of India;

And whereas the Central Government is of opinion that for the reasons aforesaid, the Council and the other organisations specified in the Schedule below are unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of opinion that because of the repeated acts of violence and attacks of the so-called Naga Army on the Security Forces and on the civil population, it is necessary to declare the Council and the other organisations aforesaid to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Naga National Council and the other organisations specified in the Schedule below, to be unlawful associations and in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

1. Federal Government of Nagaland.
2. Naga Army.
3. Kimhao (Upper House) and Tatar Hoho (Assembly of Representatives).
4. Federal Supreme Court and other bodies under it.

[No. F. 1/21/72-Poll(K).]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1972

सं० ग्रा० 569(अ).—प्रति नागा राष्ट्रीय परिषद (जो इसके द्वारा परिषद के रूप में निर्दिष्ट है)।

- (i) ने नागालैण्ड राज्य और अथवा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश (जो इसके बावजूद उक्त क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट है) के सरोपत्रती क्षेत्रों, जिनमें नागालैण्ड हैं, को मिलाकर एक स्वतन्त्र नागालैण्ड बनाने के अपने उद्देश्य को खुले रूप से घोषणा की है ;
- (ii) ने तथाकथित नागा ग्रामी नामक एक सशस्त्र बल तैयार किया है और नोबे बोगई ग्रुप्स में निर्दिष्ट संगठनों को स्थापित किया है । और वह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने तथा उक्त क्षेत्रों को भारत संघ से अलग करने के लिए उनका उपयोग कर रही है ;
- (iii) अपने उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसरण में, तथाकथित नागा ग्रामी को सुरक्षा बलों सिविल सरकार और उस क्षेत्र के नागरिकों पर आक्रमण करने तथा लुटमार आदि करने और स्थानीय सिविल जनता को भयभीत करने और उससे अव्यवस्थित घबराहट और प्रावधानों को दुरुस्त करने के लिए उपयोग कर रही है ;
- (iv) ने, उपर्युक्त उद्देश्य को पूर्ति के लिए, तथाकथित फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैण्ड के माध्यम से आर्थिक और शस्त्र संबंधी सहायता और तथाकथित नागा ग्रामी के प्रशिक्षण को सुविधाएं प्राप्त करने का दृष्टि से विदेशों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं ; और

(V) ने, उक्त पूर्वी क्षेत्र को भारत संघ से पृथक् करने के लिए एक समन्वित ग्राम्बोखन कराने के प्रयोजन से उक्त क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों और बलों को उकसाया है, उन्हें सलाह दी है और सहायता दी है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि उपर्युक्त कारणों से परिषद और नीचे की अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य संगठन गैर-कानूनी संगठन है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि निरन्तर हिंसापूर्ण कार्यों और सुरक्षा बलों और सिविल जनता पर तथाकथित नागा आर्मी द्वारा धान-बार आक्रमणों के कारण परिषद और उपर्युक्त अन्य संगठनों को तत्काल प्रभावी रूप से गैर-कानूनी घोषित करना आवश्यक है ;

अतः, अब गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निरोध) अधिनियम 1967 (1967 का 37) की धारा 3^{री} की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नागा राष्ट्रीय परिषद और नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य संगठनों को एनद्वारा गैर-कानूनी संगठन घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए यह अनुदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी किये जाने वाले किसी आदेश की सीमा के पश्चाधीन रहते हुए यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

1. फडरल गवर्नमेंट आफ नागालैंड
2. नागा आर्मी
3. किमहाओ (अपर हाउस) और सातार हो-हो (असेम्बली आफ रिप्रजेंटेटिव्स)
4. फेडरल सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीनस्थ अन्य निकाय ।

[सं० का० 1/21/72-पोल (के)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, संयुक्त सचिव ।

